दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 15 दिसम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 77

महत्वपूर्ण एवं खास

जामिया में कैब को लेकर प्रदर्शन जारी, सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं स्थगित

नईदिल्ली (आरएनएस)। नए नागरिकता कानून (कैब) के विरोध में छात्रों के जोरदार आंदोलन को देखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शनिवार को सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। सूत्रों के अनुसार कल छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस की लाठी चार्ज से छात्रों में गहरा आक्रोश है। कई छात्र बुरी तरह घायल हैं और वे परीक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं। परिसर में तनाव व्याप्त है। यह देखते हुए अगले आदेश तक विश्विद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। जामिया के मीडिया प्रभारी ने परीक्षाएं स्थगित किये जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार को आंदोलन के दौरान परीक्षाएं हुई थी लेकिन तनाव अधिक बढ़ने के कारण प्रशासन को एहतियाती तौर पर यह कदम उठाना पड़ा। अभी फिलहाल आज की परीक्षा स्थगित की गई है।

मुंडका में लकड़ी के कारखाने में भीषण आग, दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग ने एक गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया है। इस पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 21 गाड़ियां मौजूद हैं। जिस गोदाम में आग लगी है, वो प्लाईवुड का कारखाना बताया जा रहा है। आग इतनी ज्यादा है कि वो इमारत के सामने स्थित एक बल्ब फैक्ट्री तक फैल गई है। हालांकि राहत की बात ये है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने की घटना मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास हुई है। आग लगातार फैलती जा रही है। आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रहा है। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के अनुसार, यह हादसा आज सुबह करीब 5:00 बजे हुआ और अग्निशमन कर्मियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।

उत्तरी भारत में बढ़ा सर्दी का असर

नईदिल्ली (आरएनएस)। उत्तरी मैदानी इलाकों में सर्दी के कारण न्यूनतम तापमान में दो-तीन डिग्री गिरावट की आशंका के साथ ही उत्तर भारत में शनिवार को रुक रुक कर बारिश होने के साथ मध्यम से घने कोहरा छाने की संभावना है। स्काइमेट वेदर के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो गया है, जबकि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में उत्तरी हवाएं चल रही हैं। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश और एक दो बार हिमपात हो सकता है। हालांकि स्काईमेट वेदर के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में ही बना हुआ है। पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी भारत में एक उत्तरी-दक्षिणी ट्रफ बना हुआ है, जो बिहार से कर्नाटक तक फैला है। वहीं बिहार और झारखंड में गरज-चमक के साथ रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। इस सर्दी के सीजन में उत्तर भारत के पहाड़ों पर नवंबर से ही बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई थी।

मां गंगा उप-महाद्वीप की सबसे पवित्र नदीः पीएम मोदी

कानपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। परिषद को गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प का समग्र उत्तरदायित्व भी सौंप दिया गया। परिषद की प्रथम बैठक का उद्देश्य संबंधित राज्यों के सभी विभागों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों में गंगा केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान देना शामिल है।

आज की बैठक में जल शक्ति, पर्यावरण, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शहरी मामलों, विद्युत, पर्यटन, नौवहन मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के उपमुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल से कोई प्रतिनिधि बैठक में

» प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की

उपस्थित नहीं था, जबकि झारखंड से किसी प्रतिनिधि ने राज्य में जारी चुनाव और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें भाग नहीं लिया।

उन्होंने 'स्वच्छता', 'अविरलता' और 'निर्मलता' पर ध्यान केंद्रित करते हुए गंगा नदी की स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मां गंगा उप-महाद्वीप की सबसे पवित्र नदी है और इसके कायाकल्प को सहयोगात्मक संघवाद के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा का कायाकल्प देश के लिए दीर्घकाल से लंबित चुनौती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 में %नमामि गंगे% का शुभारंभ करने के पश्चात इस दिशा में बहुत कुछ किया है, जो प्रदूषण

उन्मूलन, गंगा का संरक्षण और कायाकल्प, कागज मीलों से रद्दी को पूर्ण रूप से समाप्त करने और चमड़े के कारखानों से होने वाले प्रदूषण में कमी जैसी उपलब्धियों को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ विभिन्न सरकारी प्रयासों और गतिविधियों को एकीकृत करने की एक व्यापक पहल के रूप में परिलक्षित है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

प्रथम बार, केंद्र सरकार ने पांच राज्यों जिनसे होकर गंगा की धारा बहती है और गंगा नदी में पर्याप्त जल के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 2015-20 की अवधि हेतु 20,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। नवीन अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के निर्माण के लिए अब तक 7700 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निर्मल गंगा के एक सुधारात्मक प्रारूप के लिए जनता से भी व्यापक स्तर पर पूर्ण सहयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय नदियों के किनारों पर स्थित शहरों में भी गंगा की स्वच्छता के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए जागरूकता के प्रसार की आवश्यकता होगी। योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने हेतु सभी जिलों में जिला गंगा समितियों की दक्षता में भी सुधार किया जाना चाहिए।

सरकार ने गंगा कायाकल्प परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए व्यक्तिगत, एनआरआई, कॉर्पोरेट संस्थाओं से योगदान की सुविधा हेतु स्वच्छ गंगा कोष (सीजीएफ) की स्थापना की है। माननीय प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से 2014 के बाद से उन्हें मिले उपहारों की नीलामी और सियोल शांति पुरस्कार से प्राप्त धनराशि 16.53 करोड़ रुपये सीजीएफ के लिए भेंट स्वरूप प्रदान किए।

उन्होंने गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक सतत विकास मॉडल 'नमामि गंगे' को 'अर्थ गंगा' में परिवर्तित करने की एक समग्र सोच विकसित करने का आग्रह किया। इस प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें शून्य बजट खेती, फलों के वृक्ष लगाने और गंगा के किनारों पर पौध नर्सरी का निर्माण शामिल है। इन कार्यक्रमों के लिए महिला स्व-सहायता समूहों और पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इस तरह की कार्यप्रणालियों के साथ जल से संबंधित खेलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और शिविर स्थलों के निर्माण, साइकिल और चलने की पटरियों आदि के विकास से नदी के बेसिन क्षेत्रों में धार्मिक और साहसिक पर्यटन जैसी महत्वपूर्ण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मोदी सरकार करने जा रही है ग्रेच्युटी नियमों में बड़े बदलाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ग्रेच्युटी कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के मुताबिक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी तभी मिलेगी जब वह एक संस्थान में लगातार पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नौकरी छोड़ेंगे। सरकार ने ग्रेच्युटी बिल लोकसभा में पेश कर दिया है।

नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी पाने की महत्वपूर्ण शर्तों के तहत कोई भी कर्मचारी इसके लिए तब योग्य होता है, जब वह किसी कंपनी में कम से कम पांस साल तक नौकरी कर चुका हो। सामाजिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि पांच साल तक लगातार सेवा देना उस स्थिति में अनिवार्य नहीं होगा, जब कर्मचारी की मौत या शारिरिक रुप से अक्षम होने पर नौकरी छूट जाती है। इसमें कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में ग्रेच्युटी उसके नॉमिनी को मिलेगी। यदि कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो यह राशि उसके वारिस को मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार से तमाम मजदूर संगठन लबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि ग्रेच्युटी की अवधि कम की जाए। उनका तर्क यह है कि आज के प्रतिस्पर्धा भरे दौर में लोग एक जगह टिक कर नौकरी नहीं कर पाते हैं। साथ ही तेजी से बदलते स्किल सेट और बढ़ते खर्चे के माहौल में कंपनियां भी छंटनी करती रहती हैं। ऐसे में पांच साल से पहले नौकरी जाने की आशंका बनी रहती है।

नागरिकता कानून के खिलाफ हावडा में बस को आग के हवाले किया

» गुवाहाटी में कर्फ्यू में ढील

नईदिल्ली (आरएनएस)। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और हंगामे के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। असम, त्रिपुरा में सेना तैनात है और कर्फ्यू भी लागू है।

पश्चिम बंगाल के कई शहरों में विरोध के साथ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद के सागरदीघी इलाके में महिषासुर स्टेशन पर तोड़फोड़ कर दी है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे

प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और अमित शाह के पुतले भी जला दिए हैं। इसके अलावा हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने हाइवे को बंद कर दिया। इस दौरान उनकी पुलिस के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोडने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कोना हाइवे पर एक सरकारी बस समेत कई प्राइवेट बसों में आग लगा दी।

गुवाहाटी में आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है, जबकि मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा अभी भी बंद कर रखी है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार शाम से ही इंटरनेट सेवा बंद कर रखा है। वहीं, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) ने 3 दिन के लिए सत्याग्रह का ऐलान किया। नगा स्टूडेंड्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने शनिवार को 6 घंटे के लिए बंद बुलाया है। असम में हजारों मुस्लिमों ने नागरिकता कानून के विरोध में शुक्रवार को रैली निकाली। वहीं, दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 42 छात्रों को हिरासत में लिया।

पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखकर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गुवाहाटी में अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक अभी के लिए रद्द कर दी गई है।

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार बताया कि जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रस्तावित भारत यात्रा के संदर्भ में दोनों पक्षों ने आम सहमति से फिलहाल यात्रा को टालने का निर्णय लिया है।

देश में अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसा माहौलः सोनिया

» भारत बचाओ रैली

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसा माहौल है। कांग्रेस की भारत बचाओ रैली से जनता को संबोधित करते हुए सोनिया ने पूछा कि सबका साथ, सबका विकास कहां हैं। जिस कालेधन के लिए नोटबंदी की गई थी वह कहां है। उन्होंने कहा कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं।

सोनिया ने कहा, श्अगर देश को बचाना है तो कठोर संघर्ष करना होगा। देश में बेरोजगारी का माहौल है, युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। किसान की परेशानी बढ़ गयी है। उन्हें खेती के लिए

सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आज तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है। पूरा देश पूछ रहा है कि सबका साथ, सबका विकास कहां है? कालाधन लाने के लिए नोटबन्दी की थी, लेकिन नहीं आया। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने कहा, श्आज का माहौल ऐसा हो गया है कि जब मर्जी आए धारा बदल दो, राज्य का दर्जा बदल दो, राष्ट्रपति शासन हटा दो या कोई भी विधेयक पारित कर दो। देश में अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसा माहौल है। आज रोजमर्रा चीजों की कीमत सीमा से बाहर हो गई हैं। देश के युवाओं के सामने अंधेरा है। गलत नीतियों से काम धंधे तबाह हो गए हैं। कंपनियां किसे और क्यों बेची जा रही हैं। नागरिकता कानून को लेकर उन्होंने कहा, ये लोग जो नागरिकता कानून लाए हैं, वह भारत की आत्मा को तार-तार कर देगा जैसा असम और पूर्वोत्तर में हो रहा है। ये लोग संविधान मानने का दिखावा करते हैं और हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा, श्इनका संकीर्ण एजेंडा है लोगों को लड़वाओ और अपनी नाकामी छिपाओ।श् उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, श्मोदी-शाह को बताओ कि देश बचाने के लिए हम कोई भी संघर्ष करने को तैयार हैं। इस पार या उस पार का फैसला लेना होगा।

मैं मर जाउंगा पर माफी नहीं मांगूंगा: राहुल गांधी- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज रामलीली मैदान में भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। गांधी ने कहा है कि यह हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता।

अटल घाट की सीढ़ियों पर चढ़ते समय फिसले पीएम मोदी, मची अफरातफरी

» एसपीजी के जवानों ने उन्हें उठाया

कानपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कानपुर नेशनल गंगा कांउसिल की पहली बैठक में नमामी गंगे की परियोजनाओं का हाल जाना और उसमें गिर रहे नालों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री अटल घाट पहुंचे और मां गंगा को नमन किया।

इसके बाद बोट में सवार होकर गंगा की अविरलता और निर्मलता का जायजा लिया। बोट से वह बंद हुए सीसामऊ नाले तक गए और वहां बने सेल्फी प्वाइंट को देखा। करीब 45 मिनट तक प्रधानमंत्री ने मां गंगा की गोद में बिताए। गंगा नदी में नाव से प्रदूषण तथा सफाई का जायजा लेने के बाद वापसी के समय पीएम नरेंद्र मोदी गंगा बैराज की सीढ़ियों पर फिसल गया। स्टीमर से गंगा नदी का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी को नई दिल्ली रवाना होना था। अटल घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोट पर सवार होकर मां गंगा का हाल देखा। गंगा में यात्रा के बाद वह वापस घाट पर लौटे।

एनसीबी ने 100 करोड़ की सर्वाधिक 20 किलोग्राम कोकीन जब्त की

» अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य रैकेट का खुलासा

नईदिल्ली (आरएनएस)। ऑस्ट्रेलिया में 55 किलोग्राम कोकीन और 200 किलोग्राम मेथमफेटामाइन के स्रोत की जानकारी हासिल करते हुए इन्हें जब्त किया, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन मादक द्रव्यों का मूल्य 1300 करोड़ रुपए है

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) दिल्ली क्षेत्रीय इकाई और ऑपरेशन्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अखिल भारतीय स्तर के मादक द्रव्य रैकेट का खुलासा करने में बड़ी सफलता हासिल की

है और अब तक की सबसे बड़ी मात्रा में कोकीन को जब्त किया है। भारत में एनसीबी द्वारा जब्त 20 किलोग्राम कोकीन का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 100 करोड़ रुपए के लगभग है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जब्त 55 किलोग्राम कोकीन और 200 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की कुल अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 1300 करोड़ रुपए है। अखिल भारतीय स्तर के इस रैकेट में शामिल 5 भारतीय, 1 अमेरिकी, 2 नाइजीरियाई और 1 इंडोनेशियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। भारत में इन साइकोट्रोपिक दवाओं की खेप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मंगाई गई थी। कोकीन और मेथामफेटामाइन को भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। एनसीबी की इस बरामदगी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में सक्रिय तत्वों पर दबाव पड़ा है और इस कार्रवाई के बाद इससे जुड़े विभिन्न संपर्कों को समझने और उनकी गहन जांच की जरूरत है।

आज से शुरू होगी टोल प्लाजाओं पर फास्टैग प्रणाली, पर सरकार ने दी छूट

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में रविवार 15 दिसंबर से एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिये भुगतान की सुविधा शुरू होने जा रही है। लेकिन लागू होने से ठीक एक दिन पहले सरकार ने बड़ा यू-टर्न लिया है। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि देश के कम से कम 75 फीसदी टोल लेन पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल कलेक्शन लिया जाए।

हालांकि मंत्रालय ने यह सुविधा अस्थाई तौर पर दी है। इसे पहले मंत्रालय ने डेडलाइन रखी थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने देश के सभी टोल प्लाजा पर 100 फीसदी भुगतान अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के जरिये लिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस साल जुलाई में मंत्रालय ने एक पत्र भेजा था, जिसमें टोल प्लाजा की सभी टोल लेन को एक दिसंबर तक फास्टैग लेन में बदलने के लिए कहा था। मंत्रालय ने यह फैसला टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे-लंबे जाम से छुटकारा पाने के लिए किया था। इससे पहले मंत्रालय ने फास्टैग के लागू होने की तारीख एक दिसंबर तय की थी, लेकिन 29 दिसंबर को अंतिम तिथि को 15 दिन और बढ़ाने का

फैसला लिया गया। वहीं पहले यह फैसला लिया गया था कि सभी टोल प्लाजा पर एक हाईब्रिड लेन बनाई जाएगी, जिस पर बड़े वाहनों के अलावा फास्टैग और दूसरे तरीकों से भुगतान स्वीकार किया जाएगा।

30 दिन तक छूट

मंत्रालय का कहना है कि यह अस्थाई तौर पर किया गया है और केवल 30 दिन के लिए ही लागू होगा, ताकि टोल प्लाजा पर किसी तरह की अफरातफरी न मचे और ग्राहकों को परेशानी न उठानी पड़े। सरकार का कहना है कि 15 दिसंबर से फास्टैग व्यवस्था लागू होने से पहले अभी तक 80 लाख टैग्स बांटे जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल की शुरुआत में नेशनल हाइवेज पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन 25 फीसदी थी, जो अब 40 फीसदी तक पहुंच चुका है। वहीं एनएचएआई के टोल प्लाजा पर रोजाना फास्टैग्स के जरिये 20-25 करोड़ की वेल्यू की 11 लाख ट्रांजेशन होती हैं।

आज से नंबर पोर्टेबिलिटी होगी आसान

नए नियमों के बाद ग्राहक तीन कामकाजी दिन में अपने नंबर को पोर्ट कर सकेंगे। वहीं दूसरे सर्कल में नंबर पोर्ट पांच कामकाजी दिन में पोर्ट करा पाएंगे।अभी इसमें 15-20 दिन लग जाते हैं। हालांकि पोर्टिंग कोड तभी मिलेगा जब ग्राहक सभी शर्तें पूरी करता होगा। जैसे कम से कम 90 दिन से उसके पास किसी कंपनी का सक्रिय कनेक्शन हो। उसे सभी